



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं0 पटना 528) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018

सं0 08 / आरोप-01-264 / 2014सा0-2379

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

20 फरवरी 2018

श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक-1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, छपरा के विरुद्ध विवाहित रहते हुए दूसरे विवाहित व्यक्ति से शादी करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-23 का उल्लंघन करने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में निहित प्रावधानों के तहत संकल्प ज्ञापांक-18117, दिनांक 27.11.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

वरीय उप समाहर्ता, गया के पदस्थापन से लगातार अनुपस्थित रहने संबंधी जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त सूचना के आधार पर संकल्प ज्ञापांक-16473 दिनांक 28.11.2014 द्वारा श्रीमती मिश्रा को निलंबित किया गया। कालान्तर में जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3435 दिनांक 03.03.2015 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2294 दिनांक 15.02.2016 द्वारा इनके निलंबन अवधि (दिनांक 28.11.2014 से दिनांक 03.03.2015 तक) को विनियमित करते हुए पूर्ण वेतन भुगतान का आदेश पारित किया गया।

संकल्प ज्ञापांक-18117 दिनांक 27.01.2013 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-2163 दिनांक 11.10.2014 से प्राप्त हुआ। इस आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा के उपरांत “सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए

निर्हरता होगी” संबंधी विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक-9805 दिनांक 07.07.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श माँगा गया। उक्त स्तर से पत्रांक-1488 दिनांक 31.08.2015 द्वारा प्राप्त परामर्श की सम्यक् समीक्षा के उपरान्त दंड प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी। तत्पश्चात् विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1403 दिनांक 28.01.2016 द्वारा श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1312/11 को “सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी” संबंधी दंड संसूचित किया गया।

2. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्रीमती मिश्रा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया गया। एतद्व संबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-5779/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2017 को विभागीय कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया सहित आरोप-पत्र, जाँच प्रतिवेदन एवं बर्खास्तगी आदेश (संकल्प ज्ञापांक-1403 दिनांक 28.01.2016) को निरस्त करते हुए श्रीमती मिश्रा को सेवा में पुनः स्थापित करने एवं पूर्ण परिणामी लाभ देने का आदेश पारित किया गया है। न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"For the reasons so discussed the entire proceeding initiated against the petitioner together with the chargememo bearing Memo No 18117 dated 27-11-2013, the enquiry report submitted thereon at Annexure 11, together with and the order of dismissal passed by the State bearing No 1403 dated 28-01-2016 are held illegal and passed in Violation of the statutory prescriptions underlying the 'disciplinary rules' besides resting on no evidence and are accordingly quashed and set aside. The petitioner stands restored to her post together with full consequential benefits which should be provided to her within a period of 3 months from the date of receipt production of a copy of this order.

The writ petition is allowed."

3. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर करने के विन्दू पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग भेजी गयी। इस क्रम में विधि विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया :-

“माननीय न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित न्याय AIR 1964 SC तथा 1999 (2) SC 10 मामले को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही को सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने की बात कही है तथा आरोपकर्ता द्वारा भेजे गये फोटोग्राफ को सही मानकर उसे दोषी करार दिया गया है, जो उचित नहीं है, जबकि शादी की प्रमाणिकता की जाँच नहीं करायी गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक् विचार कर के ही आदेश पारित किया गया है।

अतएव ऐसी स्थिति में मेरी राय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर करने का मामला बनता प्रतीत नहीं होता है।”

4. वर्णित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन संबंधी बाध्यकारी परिस्थितियों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई के निमित्त निम्न प्रस्ताव में अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया :-

(i) श्रीमती श्वेता मिश्रा के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1403 दिनांक 28.01.2016 को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः पदस्थापित किया जाय।

(ii) निलंबन अवधि सहित सेवा से बर्खास्तगी अवधि को सभी प्रयोजनों हेतु कर्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जाय।

(iii) श्रीमती श्वेता मिश्रा पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देगी।

5. उपर्युक्त कंडिका-04 के प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु ज्ञापांक-811 दिनांक 16.01.2018 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को संलेख भेजा गया तथा दिनांक 23.01.2018 को सम्पन्न बैठक में संदर्भित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई।

6. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

(i) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1403 दिनांक 28.01.2016 को निरस्त करते हुए श्रीमती श्वेता मिश्रा को सेवा में पुनः स्थापित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि सहित सेवा से बर्खास्तगी अवधि को सभी प्रयोजनों हेतु कर्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जाता है।

(iii) श्रीमती मिश्रा पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देगी।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 528-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>